उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) 1-1-1978 से 31-12-77 की अवधि में लाइसेंस हेतु कुल 149 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से 58 आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई, 41 को अस्वीकृत कर दिया गया तथा 38 आवेदन पत्रों को अन्य प्रकार से लाइसेंस की जरूरत नहीं थी लाइसेंस उपबन्धों से छूट दे दी गई थी फर्मों द्वारा आवेदन पत्र वापिस लिए गये थे आदि निपटा दिया गया । शेष 12 आवेदन पत्र विचाराधीन है ।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस मूल्यानुसार नहीं वरन् मात्रा के अनुसार जारी किये जाते हैं ।

(ग) वार्षिक योजनाओं में राज्यों में उद्योगों के विकास के लिए प्रावधान संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के उपरांत ही किये जाते है ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा का विलय

*608. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा को मिलाकर एक सेवा बनाने का है ;

(ख) क्या इन सेवाओं में ग्रेड चार के पदों पर भर्ती के लिये 'फीडर लिस्ट' प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है अब इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो विभाग उम्मीदवारों को ग्रेड चार के पदों पर पदोन्नत करने के लिये क्या प्रणाली बनाई गई है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) तथा (ग) : फीडर पदों से ग्रेड-IV के पदों पर पदोन्नति की विद्यमान प्रणाली अभी भी जारी है । परन्तु पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने और भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इन सेवाओं के ग्रेड-IV को पुनः संरचना किए जाने की सिफारिश की है । वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ग्रेड-IV की पुनः संरचना किए जाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय होने तक उस ग्रेड में सीधी भर्ती, नियमों में विहित पूरी सीमा तक नहीं की जा रही है । इन दोनों सेवाओं में से प्रत्येक में ग्रेड IV को कुछ रिक्तियों को समय-समय पर तदर्थ पदोन्नतियों के द्वारा भरा जा रहा है । ग्रेड-IV की पुनः संरचना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, तदर्थ व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा ।

Production of Aerated Water

*609. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) what was the production of aerated water excluding soda in millions of bottles in 1970, 1971 and 1972;

(b) what was the production in 1976 and 1977;

(c) whether there is increase or decrease in the production and reasons thereof; and

(d) whether there is any unutilized capacity in this industry, if so, how much?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). Separate figures of production of aerated water excluding soda are not maintained. The production of aerated ater (including soda) of the 35 units borne on the list of the

Directorate General of Technical Development has been as follows:—

Year	Production (in million bottles)
1970 .	917·44
1971 .	902·06
1972 .	930·00
1976 .	663·02
1977	518·02

(c) The decline in production may be attributed to restricted demand.

(d) The production indicated above in (a) & (b) has been achieved against an installed capacity of 1975 million bottles.

राजस्थान को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

*610. श्री लालजी भाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान को कैसे और क्या सहायता दी जा रही है अथवा दी जाने वाली है ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी विदेशी सरकार या एजेंसी से इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बड़ी सहायता प्राप्त हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री, श्री पी० रामचन्द्रन :

(क) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों का वित्त-पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाता है :—

(1) ग्राम विद्युतीकरण निगम ।

(2) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसके लिए धन ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से दिया जाता है; तथा

(3) राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही ।

वर्ष 1977–78 में राजस्थान के लिए 12.25 करोड़ की व्यवस्था की गई थी ।

(ख) तथा (ग) : इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार को किसी विदेशी सरकार या एजेंसी से सहायता प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, ग्राम विद्युतीकरण निगम को चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू०एस०ए०आई०डी०) से 105 करोड़ रुपये का अनुदान मिला था । निगम ने 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी०ए०) से एक करार भी किया था और इस एजेन्सी से ऋण प्राप्त किया था जिसका उपयोग पारेषण स्कीमों के लिए उपस्करों की मुख्य मदें खरीदने में किया जा रहा है सरकार के वार्षिक बजटीय आवंटनों के माध्यम से प्रथम किस्त के रूप में निगम को 57 मिलियन डालर की धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

Installation of new Broadcasting Stations under the Broadcasting Plan

*611. SHRI DHARAM VIR VASISHT: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the nature of deliberations that took place at the Sixth All India Radio and Electronics convention held at New Delhi in March 1978;

(b) whether in the Broadcasting Plan approved by I.T.U., India can possibly have 780 stations in all including 352 low power relay stations; and

(c) if so, the exact strategy of reaching out to 82 per cent population of the rural side with barely 30 per cent literacy?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) The deliberations were mainly on development of radio and TV industry, electronic components, instrumentation, research